

भारत में जल मूल्य निर्धारण सुधार: जल प्रबंधन का एक तरीका



अजय सिंह

प्रोफेसर और प्रमुख, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय,
रांची, भारत ईमेल: ajai.singh@cuja.ac.in मोबाइल 90314 50087

परिचय : डॉ. अजय सिंह ने कृषि इंजीनियरिंग, मृदा और जल संरक्षण इंजीनियरिंग और जल प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारत में आर्थिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण, सभी क्षेत्रों में पानी की मांग बढ़ रही है। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग के अनुमानों के अनुसार, अकेले सिंचाई क्षेत्र को 2010 की मांग की तुलना में 2025 तक अतिरिक्त 71 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) और 2050 तक 250 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी। प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कम हो गई है और अधिक प्रदूषित पानी और जलवायु परिवर्तन ने इसे और खराब कर दिया है। भारत में प्रति व्यक्ति जल की अनुमानित उपलब्धता 2021 में 1486 मीटर³ थी और 2031 तक घटकर 1367 मीटर³ हो जाने का अनुमान है। प्रभावी जल नीतियों और नियामक तंत्रों के कार्यान्वयन के कारण, दुनिया भर के औद्योगिक क्षेत्र ने 2016-2018 के दौरान जल निकासी में 18 प्रतिशत की कमी की है। यह उत्साहजनक है और यहां तक कि घरेलू जल आपूर्ति को भी मीटर करके निगरानी की जा रही है। हालांकि, कृषि क्षेत्र, जो सबसे अधिक पानी का उपयोग करता है,

को जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने और तेज करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर पानी की खपत को कम करने की आवश्यकता है और इसलिए, केवल जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने से एसडीजी लक्ष्य 6.4: '2030 तक' को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, सभी क्षेत्रों में जल-उपयोग दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करें और पानी की कमी को दूर करने और पानी की कमी से पीड़ित लोगों की संख्या को काफी हद तक कम करने के लिए मीठे पानी की स्थायी निकासी और आपूर्ति सुनिश्चित करें। कृषि सिंचाई के लिए सतत जल आपूर्ति को पर्याप्त जल नीतियों, बढ़ती दक्षता, घाटे की सिंचाई को अपनाने और बुनियादी ढांचे में आवश्यक निवेश के साथ जोड़कर जल उपलब्धता और सतत खाद्य उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकता है।

जल संसाधन प्रबंधन में नीतियों, नवीनतम तकनीकों, जल मांग और आपूर्ति रणनीतियों और जल शासन प्रणालियों को शामिल किया जाता है ताकि सामाजिक आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकताओं को स्थायी रूप से संबोधित किया जा सके। उचित नियामक तंत्र के साथ उचित जल नीति और

कानून पानी की मांग-पक्ष प्रबंधन और कृषि जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कई देश उचित जल संसाधन प्रबंधन रणनीति की सुरक्षा के लिए अपनी जल नीति में सुधार करना जारी रखते हैं। पहली भारतीय राष्ट्रीय जल नीति (1987) पानी की कमी के मूल्य को व्यक्त करने के लिए जल मूल्य निर्धारण की वकालत करती है। नीति में वार्षिक ओपेंडएम शुल्क और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़ी पूंजीगत लागत के एक हिस्से का भुगतान करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। यहां तक कि 1992 में वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट द्वारा भी इसकी सिफारिश की गई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रचलित जल मूल्य निर्धारण दर और संरचना और सरकारी वित्त पोषित सिंचाई परियोजनाओं में सब्सिडी के प्रावधान की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। सिंचाई जल मूल्य निर्धारण तंत्र के कार्यान्वयन से जल के कुशल उपयोग, जल संरक्षण को बढ़ावा मिलने और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होने की उम्मीद थी। हालांकि राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में मात्रात्मक जल मूल्य निर्धारण की सिफारिश की गई थी, लेकिन जल मीटरिंग बुनियादी ढांचे के खराब कार्यान्वयन के कारण इसका अभ्यास नहीं किया जाता है।

मूल्यांकन में सरलता के कारण, सिंचाई जल शुल्क क्षेत्र कवरेज और उगाई गई फसलों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। भारत में, नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। 2016 में राष्ट्रीय जल रूपरेखा विधेयक वाणिज्यिक कृषि और उद्योग पर विशेष ध्यान देने के साथ उपयोग किए गए पानी की पूरी वित्तीय लागत की वसूली को दोहराता है। विधेयक में घरेलू जल आपूर्ति के लिए एक परिवर्तनीय मूल्य निर्धारण प्रणाली को लागू करने का सुझाव दिया गया है। जल संसाधन मंत्रालय ने 2016 में एक भूजल मॉडल का मसौदा तैयार किया, जो सभी राज्य सरकारों द्वारा भूजल के विनियमन को लागू करने के लिए सरकार की चिंता को दर्शाता है। विधेयक में भूजल संसाधनों के सार्वजनिक ट्रस्टी के रूप में राज्य की भूमिका पर जोर दिया गया, जिसे सुरक्षा, संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन के लिए सामुदायिक संसाधन के रूप में माना जाना चाहिए।



भारत की सिंचाई जल आपूर्ति अवसंरचना परियोजनाएं आम तौर पर सरकार द्वारा वित्तपोषित होती हैं, जिनमें जल की मांग के प्रबंधन पर लगभग कोई विचार नहीं किया जाता है, लेकिन हाल ही में, सरकार ने जल की कमी को कम करने और सिंचाई जल की मांग को कम करने के लिए सिंचाई दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। चूंकि सिंचाई जल का उपयोग छोटे और सीमांत किसानों द्वारा किया जाता है, जो मुख्य रूप से अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि में लगे हुए हैं, सिंचाई जल का मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है और इसलिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों पर विचार करना ऐसी मूल्य निर्धारण नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जल की दरें अंतर-राज्यीय और विभिन्न फसलों के बीच भिन्न होती हैं। कुछ राज्यों में, राजस्व सृजन संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) लागत के बहुत करीब है। नहर सिंचाई जल शुल्क कम होने और कुछ राज्यों द्वारा नियमित अंतराल पर जल मूल्य निर्धारण में संशोधन न करने के कारण ओएंडएम लागत के हिस्से के रूप में सिंचाई जल के राजस्व का संग्रह धीरे-धीरे कम हो गया है। 1975-76 के दौरान, सिंचाई जल शुल्क और अन्य प्राप्तियों से लगभग 96 प्रतिशत ओएंडएम लागत पूरी की जा सकी, 1997-98 में केवल 5.8 प्रतिशत की पूर्ति की जा सकी। 2013-14

में यह हिस्सा बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत हो गया। कुछ राज्यों में स्वतंत्र जल विनियामक प्राधिकरण हैं और सिंचाई जल के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र अस्थायी है और इसमें परामर्श शामिल नहीं है। इसके अलावा, राजस्व संग्रह तंत्र भी एक बड़ा मुद्दा है और इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। सिंचाई जल शुल्क की कम प्रतिशत वसूली भूजल की भयावह कमी से दृढ़ता से जुड़ी हुई है क्योंकि जल मूल्य निर्धारण केवल सतही जल स्रोतों के लिए तय किया गया है। भूजल उपयोग के मामले में, केवल बिजली शुल्क लगाया जाता है।

भारत में अलग-अलग मूल्य निर्धारण पद्धतियाँ हो सकती हैं और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में उच्च मूल्य तय किए जा सकते हैं और पानी की प्रचुरता वाले क्षेत्रों में ढील दी जा सकती है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में, उच्च मूल्य पानी की अधिक खपत वाली फसलों को हतोत्साहित करते हैं। यदि अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है तो जलोढ़ निर्माण वाले क्षेत्रों से पानी को दुर्लभ क्षेत्रों में भी पहुँचाया जा सकता है। इससे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में अनावश्यक ड्रिलिंग से बचा जा सकेगा और भूजल को प्राकृतिक रूप से रिचार्ज किया जा सकेगा। भारत में गिरती हुई वर्षा को संग्रहित करने के लिए अधिक जल भंडारण संरचनाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसकी योजना बनाई जानी चाहिए। एक आदर्श नदी बेसिन विकसित किया जाना चाहिए, जहाँ वॉल्यूमेट्रिक मूल्य निर्धारण पद्धति को अपनाया जाए और लंबे समय तक निगरानी की जाए ताकि परिणामों का अन्य नदी

बेसिन प्राधिकरणों या राज्यों द्वारा अनुसरण किया जा सके। वर्तमान में, किसान एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं, भले ही वे कितना भी उपभोग करें। जल के दोहन के लिए परमिट प्रणाली और प्रभावी और कार्यशील नदी बेसिन आयोगों का गठन महत्वपूर्ण उपाय हैं, जिन्हें भारत में जल संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए संशोधित और लागू किया जा सकता है। बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल नीति और शासन में सुधार करना महत्वपूर्ण है। आर्थिक सिद्धांत कमी को दूर करने के लिए ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के निजीकरण की ओर झुक सकते हैं। हालाँकि, निजीकरण से आवश्यक रूप से दक्षता में सुधार नहीं होता है—यह सब किसी देश की नियामक प्रणाली की प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। भारत में जल सुरक्षा का भविष्य भी जल प्रबंधन में भावी नेताओं के हाथों में है और देशों की दबावपूर्ण जल चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रों के बीच संबंध विकसित करने के लिए सहयोग महत्वपूर्ण है।

